दिक्कतें

राज्यांश से भुगतान सुनिश्चित करने का राज्य सरकार ने दिया निर्देश

सरकार अपने मद से देगी लाभुकों को पेंशन

राज्य ब्यूरो, पटना : चालू वित्तीय वर्ष में केंद्र सरकार ने सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के मद में कुल 568 करोड़ रुपये जारी नहीं किए हैं। इसके चलते राज्य के सभी 61.67 लाख लाभुकों को मार्च से पेंशन भुगतान में परेशानी हो रही है। जबकि केंद्रांश की मांग को लेकर राज्य सरकार कई बार केंद्र से गुहार लगा चुकी है। अब राज्य सरकार अपने संसाधनों (राज्यांश) से लाभुकों के बैंक खातों में पेंशन भुगतान सुनिश्चित करने में जुटी है।

61.67 लाख लोगों के लिए चालू वित्तीय वर्ष में नहीं मिला केंद्रांश

95 फीसद लाभुकों के नाम खुल चुके हैं बैंक खाते

58.56 लाख लाभुकों के बैंक खाते

केंद्र के निर्देश पर राज्य सरकार बैंकों के सहयोग से 95 फीसद से ज्यादा लाभुकों के बैंक खाते खोलवा चुकी है। अब तक सभी 38 जिलों में कुल 58.56 लाख लाभुकों के नाम से बैंक खाते खुल चुके हैं। अब मात्र 3.11 लाख ऐसे लाभुक बचे हैं जिनके बैंक खाते नहीं हैं। इस माह में इनके खाते खोलवा दिए जाएंगे। इसके लिए अभियान चलाया जा रहा है।

बुधवार को समाज कल्याण मंत्री मंजु वर्मा ने समीक्षा के दौरान इतनी बड़ी संख्या में लाभुकों के बैंक खातों को खुलवाने और उनके नाम का सत्यापन कराने के लिए अफसरों की तारीफ की।

सभी बैंक खाते केंद्र सरकार के पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्ट (पीएफएमसी) से जुड़े हैं जो पें भुगतान की पूरी प्रक्रिया को पार बनाने में मदद करेगा।

केंद्रांश नहीं मिलने से सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से संबंधित लाभुकों को पेंशन भुगतान में काफी परेशानी हो रही है। हर साल जून तक केंद्रांश की राशि उपलब्ध हो जाती थी, लेकिन इस बार केंद्र सरकार में संबंधित मंत्री से जाकर मेरे अनुरोध करने के बावजूद केंद्रांश जारी नहीं किया गया है। इसके बावजूद राज्य सरकार से प्राप्त राज्यांश से लाभुकों को पेंशन भुगतान सुनिश्चित कराया जा रहा है।

मंजु वर्मा, मंत्री, समाज कल्याण विभाग